हैं जबकि अधिनियम को पारित हुए 24 वर्ष तथा वार्षिक कार्यक्रम को तैयार किए 10 वर्ष हो चुके हैं ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) जल भूतल परिवहन मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की एक बैठक 9-2-87 को हुई थी।

इस मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति में पर्यवेक्षक के रूप में किसी गैर-सरकारी सदस्य को नामित नही किया गया है । तथापि, कुछेक अधीनस्थ कार्यालयों ने अपनी राजभाषा कार्यान्वयन समितियों में पर्यवेक्षकों के रूप मे हिन्दी सलाहकार समिति के स्थानीय सदस्यों को नामित किया है। इस मुद्दे पर और प्रश्न के भाग (ख) और (ग) के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

राजभाषा अधिनियम का लागू किया जाना

433. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **रेल** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मत्रालय से सम्बद्ध हिन्दी सलाहकार समिति की इस वर्ष कितनी बैठकें हुई और राजभाषा कार्यान्वयन समिति मे सभी स्तरो पर गैर-सरकारी सदस्यो को पर्यवेक्षक के रूप में नामित किए जाने के सम्बन्ध मे क्या स्थिति है ;

(ख) मत्रालय, इसके विभागो, संस्थानो और अधीनस्थ कार्यालयो मे, हिन्दी अनुभाग को छोड़कर किस-किस अनुभाग मे शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जा रहा है तथा यह किस-किस तारीख से किया जा रहा है तथा किन मामलों मे हिन्दी को अब तक नहीं अपनाया गया है तथा इसके क्या कारण है ; और

(ग) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) को मंत्रालय स्तर से निम्नतम स्तर तक पालन न किए जाने के क्या कारण हैं जबकि अधिनियम को पारित हुए 24 वर्ष तथा वार्षिक कार्यक्रम को तैयार किए 10 वर्ष हो चुके हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) चालू वर्ष के दौरान अब तक रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति की तीन बैठकें हो चुकी हैं। रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति के गैर-सरकारी सदस्य, रेलवे बोर्ड कार्यालय और क्षेत्रीय/उत्पादन कारखानो आदि की प्रधान कार्यालय स्तर पर गठित राजभाषा कार्यान्वयन समितियों मे पहले से ही प्रेक्षक सदस्य के रूप में नामित है।

(ख) और (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

राजभाषा अधिनियम का लागू किया जाना

434. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय से सबद्ध हिन्दी सलाहकार समिति की इस वर्ष कितनी बैठकें हुई और राजभाषा कार्यान्वयन समिति मे सभी स्तरो पर गैर-सरकारी सदस्यो को पर्यवेक्षक के रूप मे नामित किये जाने के संबंध में क्या स्थिति है ;

(ख) मत्रालय, इसके विभागों, संस्थाओं और अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी अनुभाग को छोड़कर किस-किस अनभाग मे शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जा रहा है तथा यह किस-किस तारीख से किया जा रहा है तथा किन मामलों में हिन्दी को अब तक नही अपनाया गया है तथा इसके क्या कारण है ; और

(ग) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) को मंत्रालय स्तर से निम्नतम स्तर तक पालन न किए जाने के क्या कारण है जबकि अधिनियम को पारित हुये 24 वर्ष तथा वार्षिक कार्यक्रम को तैयार किये 10 वर्ष हो चुके है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) वर्ष 1987 में, 14-1-87 को हिन्दी सलाहकार समिति की एक बैठक हुई थी। मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के कोई भी गैर-सरकारी सदस्य मंत्रालय के विभागों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों में पर्यवेक्षक के रूप में नहीं रखे गये हैं।

(ख) यद्यपि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसके विभागों, संस्थाओं और अधीनस्थ कार्यालयों में शत-प्रतिशत काम हिन्दी में नहीं हो रहा है तथापि राजभाषा अधिनियम, नियमों और अन्य निर्देशों को लागू करने के लिये किये गये प्रयासों के परिणाम निकल रहे हैं और सरकारी काम-काज में हिन्दी का प्रयोग उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। इस समय शिक्षा विभाग में संस्कृत और भाषा प्रभागों में तथा केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय और वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग नामक इसके अधीनस्थ कार्यालयों में अधिकांश काम हिन्दी में ही हो रहा है। 26-10-87 को संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप-समिति द्वारा किये गये शिक्षा विभाग के निरीक्षण में की गई सिफारिशों के अनुसरण में यह मंत्रालय शिक्षा विभाग के भाषा और संस्कृति प्रभागों में शत-प्रतिशत काम हिन्दी में ही करने के लिये विचार कर रहा है।

(ग) कला विभाग, जहां हिन्दी एकक अभी स्थापित किया जाना है, को छोड़कर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सभी विभागों में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) में की गई व्यवस्थाओं का यथा-संभव पालन किया जा रहा है।

राजभाषा अधिनियम का लागू किया जाना

435. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) उनके मंत्रालय से संबद्ध हिन्दी सलाहकार समिति की इस वर्ष कितनी बैठकें हुई और राजभाषा कार्यान्वयन समिति में सभी स्तरों पर गैर-सरकारी सदस्यों को पर्यवेक्षक के रूप में नामित किये जाने के संबंध में क्या स्थिति है;

(ख) मंत्रालय, इसके विभागों, संस्थाओं और अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी अनुभाग को छोड़कर किस किस अनुभाग में शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जा रहा है तथा यह किस-किस तारीख से किया जा रहा है तथा किन मामलों में हिन्दी को अब तक नहीं अपनाया गया है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) को मंत्रालय स्तर से निम्नतम स्तर पर पालन न किये जाने के क्या कारण है जबकि अधिनियम को पारित हुये 24 वर्ष तथा वार्षिक कार्यक्रम को तैयार किये 10 वर्ष हो चुके हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) वर्तमान वर्ष के दौरान हिन्दी सलाहकार समिति की एक बैठक हुई है और दूसरी बैठक दिसम्बर, 1987 में बुलाई गई है। इस समय मंत्रालय के सात अधीनस्थ कार्यालयों और स्वशासी निकायों ने अपनी-अपनी राजभाषा कार्यान्वयन समितियों में गैर-सरकारी सदस्यों को प्रेक्षकों के रूप में नामित किया है।

(ख) और (ग) राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का मंत्रालय में पालन किया जा रहा है। इस अधिनियम के उपबंधों का पालन करने के लिये जोरदार प्रयास किये जा रहे है। हिन्दी में करने के लिये अपेक्षित सभी सरकारी काम नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुसार हिन्दी में किया जा रहा है।

Development of Calcutta Airport

436. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to develop Calcutta Airport during the Seventh Five Year Plan;